

राज्य वक्फ बोर्ड को सशक्त और प्रभावी बनाने हेतु सरकार गंभीर-उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आश्वासन

मुसलमानों की शैक्षणिक, चिकित्सा और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे



समीर काज़ी की प्रभावशाली प्रतिनिधित्व की सराहना

मुंबई, २९ अप्रैल: जमीर काज़ी और अज़ीज़ एजाज़ कि रिपोर्ट): महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज के लिए एक आशाजनक संकेत देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और इस बोर्ड को एक सक्रिय, स्वायत्त और पारदर्शी संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि मुस्लिम समुदाय की भलाई में वक्फ की भूमिका सशक्त रूप से सामने आए।

मंत्रालय में आयोजित एक अहम बैठक में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति, वक्फ

संपत्तियों की सुरक्षा और उनके बेहतर उपयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने की, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दत्तात्रेय भर्से, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अजित पवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की अमानत हैं और उनका संरक्षण, विकास और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में वक्फ बोर्ड की स्वामित्व वाली जिन इमारतों का निर्माण अधूरा है, उन्हें

उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा ताकि ये संस्थाएं आने वाले दशकों तक मुसलमानों की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि ये इमारतें केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनी हैं, बल्कि ये मुस्लिम समाज की तरक्की के प्रतीक स्तंभ हैं।

बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार से जुड़ी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की ठोस नीति पर चर्चा की गई। अजित पवार ने कहा कि मुसलमानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एक गरिमायुक्त भागीदार बनाना सरकार का उद्देश्य है। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से शिक्षा, स्कॉलरशिप,

व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्यम विकास की योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जाएगा ताकि मुस्लिम युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम युवाओं को केवल शिक्षा नहीं, बल्कि हुनर, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएं जिनका सीधा लाभ अल्पसंख्यकों को मिले। ऐसे संस्थानों को केवल कागज़ी आंकड़ों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि यह व्यावहारिक विकास का माध्यम बनें।

बैठक में राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता, फंड्स की समयबद्ध आपूर्ति और निर्णय लेने में स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। अजित पवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड को एक स्वायत्त, दक्ष और जवाबदेह संस्था बनाना समय की आवश्यकता है, ताकि यह मुस्लिम समाज की सेवा और नेतृत्व का उत्तरदायित्व अच्छे ढंग से निभा सके।

बैठक में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काज़ी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सैयद समेत अन्य मुस्लिम अधिकारियों की भागीदारी को सरकार ने इस बात का संकेत बताया कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व अब केवल प्रतीकात्मक नहीं,

बल्कि व्यवहारिक स्तर पर हो रहा है। यह पहल मुस्लिम नेतृत्व को यह भरोसा देगी कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है। अंत में अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों को एक सम्मानजनक, समृद्ध और सुरक्षित जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई जगह नहीं है। हमें मिलकर एक ऐसा महाराष्ट्र बनाना है जहाँ हर धर्म, जाति और वर्ग को समान अवसर प्राप्त हों।

इस पूरी प्रक्रिया में चेयरमैन समीर काज़ी की रुचि और प्रयासों की विशेष प्रशंसा की गई।

बेटे की मौत का दुख सह न सकी मां, विष सेवन कर छोड़ दिए प्राण

मां-बेटे की दुखद घटना से गेवराई क्षेत्र शोकाकुल

गेवराई, २९ अप्रैल (प्रतिनिधि): तालुका के वाहेगाव आम्ला गांव में कर्ज के बोझ से परेशान बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे की मौत का सदमा न सह पाने पर अगले ही दिन मां ने भी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस हृदयविदारक घटना से गेवराई तालुका में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहेगाव आम्ला गांव निवासी अभिमान खेतेरे (उम्र ४५ वर्ष) ने सोमवार (दिनांक २८) को दोपहर में कर्ज से

पेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे की मृत्यु की खबर मिलते ही उनकी मां कौशल्या भागुजी खेतेरे (उम्र ६० वर्ष) गहरे मानसिक तनाव में आ गई और उन्होंने भी

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया-अॅड.सर्जेराव तांदळे

जयदत्त नगर और रुई लिंबा क्षेत्र के विकास कार्य पंकजाताई मुंडे के माध्यम से पूर्ण करेंगे-आश्वासन

बीड (प्रतिनिधि): दिनांक २८ अप्रैल २०२५, सोमवार को बीड तालुका के रुई लिंबा गांव में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर देशमुख, जिला सरचिटणीस एड. सर्जेराव तांदळे, संगठन सरचिटणीस देविदास नागरगोजे, उपाध्यक्ष नवनाथ अण्णा शिराळे, शांतिनाथ डोरले समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में एडवोकेट तांदळे ने कहा कि आज जो देश का शासन व्यवस्था,



कानून और संविधानिक प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है, उसका श्रेय पूरी तरह से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जाता है। उन्होंने ही समाज के सबसे पिछड़े, बंचित और गरीब तबके को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया। आज हर वर्ग को न्याय, शिक्षा और नौकरी के समान अवसर उन्हीं के कारण प्राप्त हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आज कई पिछड़े वर्ग के युवा डॉ. आंबेडकर की प्रेरणा और संविधान द्वारा मिले अधिकारों के कारण आईएसएस, आईपीएस जैसे उच्च पदों पर पहुँच चुके हैं। एड. तांदळे ने कार्यक्रम में यह भी आश्वासन दिया कि जयदत्त नगर और आस-पास के क्षेत्रों के जो भी विकास कार्य लंबित हैं, उन्हें केंद्रीय नेता पंकजाताई मुंडे के माध्यम से शत-प्रतिशत पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गली से दिहरी तक आज हमारी सरकार है, इसलिए अच्छे और सकारात्मक कार्यों में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में लहू लगड, गणेश म्हेत्रे, दलित पैंथर के जिला अध्यक्ष नितीन सोनवणे, सचिन तिपटे, गणेश प्रभू पवार, महादेव उद्धव ओव्हाळ, राहुल कचरू कांबळे, प्रभू नामदेव पवार, सतीश दशरथ सोळुंके, सागर सुरेश सोळुंके, अशोक गायकवाड सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस सफल कार्यक्रम का आयोजन विकास वाव्हळ द्वारा किया गया था।

रेलवे पटरी पर मिला युवक का शव बीड नगर परिषद द्वारा निकाले गए सभी टेंडर रद्द

मलकापुर शिवार में मिली लाश से हत्या की आशंका फारुख पटेल, अशफाक इनामदार के रिटायरमेंट के बाद लिया गया निर्णय, जल्द शुरू होगी नई प्रक्रिया

परळी, २९ अप्रैल (प्रतिनिधि): परळी ग्रामीण पुलिस थाने की सीमा अंतर्गत मलकापुर शिवार के रेलवे ट्रैक पर मंगलवार (२९ अप्रैल) सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जानकारी में कहा गया कि युवक रेल यात्रा के दौरान गिरा होगा, लेकिन शव पटरी के बीचोंबीच पाए जाने से हत्या की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इस प्रकरण की जांच परळी पुलिस कर रही है।

मंगलवार सुबह कुछ स्थानीय लोगों को मलकापुर शिवार स्थित रेलवे पटरी पर युवक का शव दिखाई दिया। शव के सिर पर गंभीर

चोट के निशान थे और घटनास्थल पर खून फैला हुआ था। सूचना मिलने पर परळी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।

दोपहर में मृतक की पहचान कर ली गई, जो उदगीर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यात्रा करते समय गिरने से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन शव रेलवे पटरी के बीचोंबीच पड़ा होने के कारण घटना पर संदेह जताया जा रहा है।

यह दुर्घटना है या किसी प्रकार का षड्यंत्र, इसकी गहराई से जांच परळी पुलिस द्वारा की जा रही है।

बीड (प्रतिनिधि): बीड नगर परिषद ने सफाई कार्य, कचरा उठाव और अन्य विभागीय ठेकेदारियों से संबंधित करीब आठ करोड़ रुपये के टेंडर रद्द कर दिए हैं। इनमें ई-लायब्ररी, डिजिटल क्लासरूम समेत कुल ५० से अधिक टेंडरों को शामिल किया गया था।

स्वच्छता विभाग से जुड़े ठेकेदारों द्वारा पिछले कई वर्षों से कार्य किया जा रहा था। अब इनकी अवाधि पूर्ण होने के बाद यह निर्णय लिया गया

नगर परिषद के पूर्व सभापति फारुख पटेल और तत्कालीन मुख्याधिकारी अशफाक इनामदार के रिटायरमेंट के बाद नये प्रशासन ने यह बड़ा निर्णय लिया है।

नगर परिषद के नये मुख्याधिकारी शुद्धीपकक काले ने कहा कि ये सारे टेंडर अब रद्द कर दिए गए हैं और जल्द ही नई प्रक्रिया

शुरू की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उठाया गया है।

पहलगाय हमले में मारे गए नागरिकों के परिजनों को ५० लाख रुपये और सरकारी नौकरी: देवेंद्र फडणवीस मुंबई (प्रतिनिधि): पहलगाय

आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से ५० लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाएगी, यह घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है।

भीख मांगने वाले व्यक्तियों को अब मिलेगा ४० रुपये प्रतिदिन मेहनताना, ६१ वर्षों में पहली बार बदलाव

मुंबई: भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भिक्षागृहों में रहने वाले व्यक्तियों को अब ५ रुपये की जगह ४० रुपये प्रतिदिन मेहनताना देने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

१९६४ से अब तक सिर्फ ५ रुपये प्रतिमाह मेहनताना दिया जाता था। अब ६१ साल बाद इसमें बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र में १४ भिक्षागृह संचालित किए जाते हैं, जिनमें करीब ४१२७ व्यक्तियों का पुनर्वास होता है। उन्हें कृषि व लघुउद्योग प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। नया

निर्णय उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना (झूच-ध-ड-डतख) को राज्य में लागू करने को मंजूरी ओबीसी और डीएनटी वर्गों के छात्रों को केंद्र सरकार की मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छा